

## राजेश्वर प्रसाद बनाम आयकर आयुक्त

(जी. सी. मित्तल )

इसलिए, राम का मामला सही ढंग से तय नहीं किया गया है और इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है। नानक सिंह एच के मामले में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जुर्माने की राशि, यदि भुगतान किया जाता है, तो मुआवजे के भुगतान की ओर मोड़ दिया। जुर्माने के अधिरोपण को सजा के रूप में दरकिनार कर दिया गया था। नानक सिंह के मामले में अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रावधानों का सही दृष्टिकोण लिया गया है।

(14) अंदर। मामले में, मुआवजे की प्राप्ति के लिए कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं हो सकती है क्योंकि जुर्माना जो पहले से ही निचली अदालत के आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किया गया था, उसे मुआवजे में बदल दिया गया है,

(15) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, हम इस संशोधन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं।

### एस. पी. गोयल और जी. सी. मित्तल के समक्ष

राजेश्वर प्रसाद-आवेदक,

बनाम

द कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स, हरियाणा-रेसपोण्डेंट।

आयकर संदर्भ सं. 1977 का 92. 10 जुलाई, 1985।

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा यथा संशोधित-धारा 2 (14) (ii)-आभूषण बेचने पर पूंजीगत लाभ-संशोधन अधिनियम वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल के दिन से प्रभावी किया गया-ऐसा संशोधन-चाहे वह उस वर्ष या उसके बाद के वर्ष के निर्धारण पर लागू हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब आयकर अधिनियम, 1961 का किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन संशोधन किया जाता है, तो संशोधन उस वर्ष के निर्धारण पर लागू होना चाहिए। अधिनियम में कोई भी संशोधन जो किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन के बाद लागू होता है, उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू नहीं होगा, भले ही मूल्यांकन वास्तव में संशोधनों के लागू होने के बाद किया गया हो। इस प्रकार, जब किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन आभूषणों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ को कर के लिए उत्तरदायी बनाने वाला संशोधन लागू होता है, तो वह संशोधन उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू होगा।

(Para 7).

संदर्भ आयकर अपीलीय अधिकरण चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ द्वारा इस माननीय उच्च न्यायालय की राय के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 (1) के अधीन 20 अक्टूबर, 1976 के अधिकरण आदेश से उद्धृत विधि के निम्नलिखित प्रश्न पर आयकर अपील सं. 1975-76 का 171. & amp; R.A. नहीं। निर्धारण वर्ष 1973-74 के संबंध में 1976-77 का 171.

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर और 1 अप्रैल, 1973 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (14) (ii) के संशोधन को ध्यान में रखते हुए अधिकरण को यह अभिनिर्धारित करने में विधि द्वारा न्यायोचित ठहराया गया था कि आभूषणों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए करयोग्य थी?"

8. एस. गुप्ता, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

अशोक भान सीनियर अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता अजय मित्तल

### न्यायाधीश जी.सी. मित्तल,

1. यदि आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) में एक संशोधन लाया जाता है किसी विशेष वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी, "क्या वह संशोधन उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू होगा" यह कानून का प्रश्न है जिसे इस संदर्भ में निर्धारित करने के लिए हमें बुलाया गया है,

2. वर्ष 1972-73 के दौरान जो 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुआ, एल. राजेश्वर प्रसाद (इसके बाद "निर्धारिती" कहा जाएगा) ने आभूषण/आभूषण रुपये में बेचे। 56,500. निर्धारिती के अनुसार, आभूषणों की बिक्री पर कोई पूंजीगत लाभ अर्जित नहीं हुआ। हालाँकि, आयकर अधिकारी निर्धारिती के रुख से सहमत नहीं थे और चूंकि संशोधन धारा 2(14)(ii) में शामिल था। अधिनियम 1 अप्रैल, 1973 को लागू हुआ, यह माना गया कि मूल्यांकन वर्ष 1973-74 में, संशोधित प्रावधान के कारण, आभूषणों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाना था। आवश्यक कटौतियों आदि की अनुमति देने के बाद, शुद्ध पूंजीगत लाभ रुपये पर निर्धारित किया गया था। 24,550.

3. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर मामला अपील अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील में उठाया गया जहां भी निर्धारिती असफल रहा।

4. ट्रिब्यूनल में आगे की अपील का भी यही हथ्र हुआ (कॉपी अनुलगनक "डी")।

5. कानून के बिंदु तय करने में, ट्रिब्यूनल ने करीमथारुवी टी एस्टेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। a i=2> [1966] 60 आईटीआर 262।

6. अधिनियम की धारा 256(1) के तहत आवेदन पर, ट्रिब्यूनल ने राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न इस अदालत को भेजा है:

"क्या, तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों पर और धारा 2(14)(ii)

7. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और करीमथारुवी टी एस्टेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य को पढ़ने के बाद [1966 ] 60 आईटीआर 262, हम पाते हैं कि ट्रिब्यूनल का निर्णय सही है और प्रश्न का उत्तर सकारात्मक यानी राजस्व के पक्ष में दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है (हेडनोट):

"अब, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि आयकर अधिनियम, क्योंकि इसे अप्रैल के पहले दिन संशोधित किया गया है किसी भी वित्तीय वर्ष को उस वर्ष के आकलन पर लागू होना चाहिए। अधिनियम में कोई भी संशोधन जो किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन के बाद लागू होता है, उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू नहीं होगा, भले ही मूल्यांकन वास्तव में संशोधनों के लागू होने के बाद किया गया हो।"

8. वर्तमान मामले में, संशोधन 1 अप्रैल, 1973 को लागू हुआ, और इसलिए, चूंकि आभूषणों/आभूषणों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ पर कर लगाया गया था, इसलिए ट्रिब्यूनल अधिकारियों के निर्णय की पुष्टि करने में सही था। कर लगाने में नीचे.

9. श्री बलवंत सिंह गुप्ता द्वारा यह तर्क देने की मांग की गई थी कि कुछ संशोधनों में, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि किस मूल्यांकन वर्ष के लिए वही लागू होगा और चूंकि प्रश्न में संशोधन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यह आकलन वर्ष 1973-74 पर लागू होगा, संशोधन केवल अगले वर्ष, यानी 1974-75 में प्रभावी होगा। संशोधन करते समय अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब भी किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से संशोधन किया जाता है, तो उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, संशोधन उसके लिए किए जाने वाले आकलन पर लागू होगा। वर्ष और ट्रिब्यूनल ने यही कहा है और हम उससे सहमत हैं।

10. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम प्रस्तावित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देते हैं, अर्थात्, राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अगले वर्ष, i.e., 1974-75। संशोधन करते समय विभिन्न वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब भी किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से संशोधन किए जाते हैं, तो उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कथन के अनुसार संशोधन उस वर्ष के लिए किए जाने वाले आकलनों पर लागू होगा और यही अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है और हम इससे सहमत हैं।

(10) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम राजस्व के पक्ष में और टीएचजी निर्धारिती के खिलाफ सकारात्मक, i.e. में प्रोप प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

---

**अस्वीकरण:** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

अनुराग यादव  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
नारनौल, हरियाणा